बदलाव के 2 साल

सक्षम किसान - समृद्ध भारत

सत्यमेव जयते

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू करें तो हम देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा बल दे सकते हैं।

– श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

कृषि को दोगुना आवंटनः

कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण की राशि को 15,809 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 35,984 करोड़ रूपये कर दिया गया है। सिंचाई के लिए नाबार्ड के सहयोग से 20,000 करोड़ रूपये की लंबी अवधि का कार्पस फंड तैयार किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए रु. 12,517 करोड़ के माध्यम से 23 योजनाएं पूरी की जाएंगी।

किसानों को कैसे होगा लाभ?

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत ही कम प्रीमियम पर पूरा बीमा।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की बेहतर सुविधाएं, लंबी अवधि का सिंचाई फंड, भूजल के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा कुएं और तालाब।
- कर्ज के ब्याज की वापसी का दबाव कम करने के लिए 15,000 करोड़ रूपये का आवंटन।
- कृषि ऋण प्रवाह को बढ़ाकर 9 लाख करोड़ कर दिया गया है।
- गांवों की सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बढ़ावा।
- गन्ने के किसानों के लिए प्रभावी नीतिगत फैसले।
- गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अरबन मिशन की शुरूआत।
- बिचौलियों को हटाने हेतु सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एवं ई–ट्रेडिंग प्लेटफार्म पायलट प्रोजक्ट प्रारम्भ, जिससे किसान अपना उत्पाद फायदे वाले कृषि मंडियों में सुगमता से बेचकर अधिक लाभ उठा सकेंगे।
- बागवानी उत्पादन और प्रबंधन हेतु रिमोट सेन्सिंग प्रौद्योगिकी तकनीक का विकास कर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल, गेहूं, दलहन फसलों के अलावा मोटे अनाज, गन्ना, जूस एवं कपास आदि को शामिल कर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- गरीब किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए सरकार ने गतिविधियां तेज की हैं।
- किसानों तक शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता वाले बीज पहुंचे, इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम की क्षमता को बढ़ा दिया गया है।

- श्वेत एवं नीली क्रांति पर मोदी सरकार का विशेष जोर।
- कुक्कुट कार्यकलापों में उद्यमशीलता का विकासः राष्ट्रीय पशुधन के घटक उद्यमशीलता विकास और रोजगार सृजन (ईडीईजी) के अधीन सरकार के पास कुक्कुट कार्यकलापों के माध्यम से प्रचुर कुक्कुट प्रजनन फार्म की स्थापना करना और डक/टर्की/गुनिया फाउल/जापानी बटेर, आहार गोदाम, आहार मिल, आहार विश्लेषण प्रयोगशाला, अण्डा ग्रेडिंग, पैकिंग और निर्यात क्षमता बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इस दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है।
- कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार पर विशेष बल।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना–कृषि और गांवों को बिजली सप्लाई के लिए अलग फीडर बनाना।
- दीनदयाल अन्त्योदय मिशनः सूखे एवं ग्रामीण आपदा से निपटने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह का गठन करना जो मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं की जांच एवं जल संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा और हर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन का चयन करेगा।
- अटल पेंशन योजना।
- यूरिया पर नीम की परत – उर्वरक की क्षमता में बढ़ोतरी और अन्य प्रयोगों को रोकना।
- किसान टीवी– किसानों को मौसम, किसान मंडी और अन्य आंकड़ों में मदद के लिए सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे का चैनल।
- ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपये का अनुदान। यूपीए सरकार के पूर्ववर्ती 5 साल की तुलना में 228 प्रतिशत की जबरदस्त छलांग।
- डिजिटल साक्षरता अभियान योजना : 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को शामिल करने की योजना ।
- अघोषित आय का 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाए गए अधिभार को 'कृषि कल्याण अधिभार' कहा जाएगा, जिसका उपयोग कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत राशि का लक्ष्य बढ़ाकर 1.80 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव।
- गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा। 3 साल में 5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
- 2.5 लाख अनुसूचित जाति–जनजाति और महिला उद्यमियों की भलाई के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना।
- 2016–17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खोले जाएंगे।

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः

- माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बीमा योजनाओं की विसंगतियों को दूर कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में लागू की गई है।
- **फसल बीमा में यह सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है।**
- खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फसलों के लिए **एक मौसम, एक दर** होगी – जिलेवार और फसलवार अलग–अलग दर से अब मुक्ति मिलेगी– खरीफ – सिर्फ 2 प्रतिशत– रबी : सिर्फ 1.5 प्रतिशत
- फलस्वरूप किसानों के लिए यह अब तक की **सबसे कम प्रीमियम दर** होगी। शेष भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा– 90 प्रतिशत से ज्यादा होने पर भी।
- **पूरा संरक्षण मिलेगा** – बीमा पर कोई भुगतान सीमा (कैपिंग) नहीं होगी और इसके कारण दावा राशि में कमी या कटौती भी नहीं होगी।
- यदि खराब मौसम के कारण किसान बुआई/रोपाई नहीं कर पाते हैं, तब भी वे बीमे के दावे का हकदार होंगे।
- पहली बार देश भर में फसल कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, बेमौसम बारिश एवं स्थानीय आपदा जैसे ओले, जमीन धंसने व जल भराव से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है।
- पहली बार सही आकलन और शीघ्र भुगतान के लिए मोबाइल और सैटेलाइट टेक्नालॉजी के व्यापक उपयोग पर जोर दिया गया है।
- इस योजना का मीडिया के जरिये व्यापक जागरूकता व प्रचार प्रसार करने का बड़े पैमाने पर प्रावधान किया गया है, जिससे वर्तमान में 20 प्रतिशत बीमित किसानों की संख्या अगले 2–3 वर्षो में बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा सके
- 2016–17 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आबंटन 5,500 करोड़ रुपये किया गया है जो पिछले बजट में 3185 करोड़ रूपय था। इस प्रकार इस मद में लगभग 73 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

2. आपदा राहत के मानकों में परिवर्तनः

- आपदा से पीड़ित किसानों को राहत पहुँचाने के मामले में मोदी सरकार ने मानकों में परिवर्तन किया है, पहले 50 प्रतिशत से अधिक फसल का आपदा से नुकसान होने पर जो मुआवजा मिलता था वह अब 33 प्रतिशत पर प्राप्त होगा। भुगतान की राशि को भी डेढ़ गुना कर दिया गया है।

- अतिवृष्टि से खराब हुए टूटे और कम गुणवत्ता वाले अनाज का भी पूरा समर्थन मूल्य देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों को पहले जहां मात्र 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान था उसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है।

- वर्ष 2010–2015 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में 33580.93 करोड़ रूपये स्वीकृत किए थे, जबकि वर्ष 2015–2020 के लिए ये राशि बढ़ाकर 61,220 करोड़ रूपये कर दी है। वर्ष 2016–17 के लिए एसडीआरएफ से सूखा प्रभावित 10 राज्यों को पहली किश्त के तौर पर रू 2551 करोड़ जारी किए गए है, जिनका उपयोग चारे या पशु शिविरों के लिए जल आपूर्ति, पशु शिविरों के बाहर पशुओं के लिए चारा भेजने, हैंड पंप की मरम्मत और रिंग वेल आदि के लिये किया जा सकता है।

- इसी प्रकार सूखा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित राज्यों को यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान चार वर्षों 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 में एनडीआरएफ से जहां राज्यों द्वारा रू. 92043.49 करोड़ की सहायता राशि की मांग की गई, वहां रू. 12516.20 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। वहीं एनडीए सरकार द्वारा मात्र एक वर्ष 2014–15 में राज्यों द्वारा मांगे गए रू. 42021.71 करोड़ के सापेक्ष रू. 9017.998 करोड़ स्वीकृत किए गए। वर्ष 2015–16 में राज्यों द्वारा रू. 41,722.42 करोड़ की मांग के सापेक्ष अब तक रू.13,496.57 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं।

- एनडीआएफ के तहत केंद्र शासित राज्यों के लिए सहायता की कोई योजना नहीं थी। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने 2015–16 में केन्द्र शासित आपदा राहत कोष (यूटीडीआएफ) के लिए रू. 50 करोड़ का आवंटन किया।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः

- सूखे की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना के क्रियान्वयन में तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं।

- इस योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा जिसके लिए नए बजट में 2016–17 के लिए 5717 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रावधान है। जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 2015–16 की तुलना में रु.1550 करोड़ के बदले रु.2340 करोड़ आवंटित करना है जो कि पिछले वर्ष का 51 प्रतिशत अधिक है, इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) तथा सूखा प्रूफिंग और जल संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।

- वर्ष 2013–14 में 4.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र व वर्ष 2014–15 में 4.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया था।

- वर्ष 2015–16 में 5.7 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया

है। इस वर्ष 2016–17 में 8.3 लाख हैक्ट्येयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है।

- वृहद एवं मध्यम 89 सिंचाई परियोजनाएं 15–20 वर्षों से लंबित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अगले पांच वर्ष में रू. 86,500 करोड़ की आवश्यकता है। इससे 80.6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है।
- वर्ष 2016–17 के लिए रु. 12,517 करोड़ के माध्यम से 23 योजनाएं पूरी की जाएंगी।
- इसके अतिरिक्त इस वर्ष नाबार्ड के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ का सिंचाई फण्ड सृजित करने का फैसला किया गया है।
- मनरेगा के तहत वर्षापोषित क्षेत्रों में 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं की व्यवस्था होगी।
- प्रत्येक किसान के खेत को सिंचाई का पानी पहुँचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है।
- जिला सिंचाई योजना में एकरुपता लाने के लिए टैंपलेट विकसित एवं राज्यों के साथ इसे साझा किया।
- 31 मार्च, 2016 तक 235 जनपदों के जिला सिंचाई योजनाएं तैयार कर ली गईं हैं। 30 सितम्बर, 2016 तक शेष जनपदों की जिला सिंचाई योजनाओं को तैयार कर लिया जाएगा।
- वर्ष 2015–16 में जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के लिए रुपये 65 करोड़ 40 लाख की राशि दी गई।
- वर्ष 2015–16 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आवंटित राशि में से रुपये 175 करोड़ देश के भू–जल की समस्या से सबसे अधिक ग्रसित केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा चिन्हित 150 ब्लॉक में मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु पक्के निर्माण कार्यों में सामग्री घटक को पूरित करने हेतु–राज्यों को आवंटित एवं विमुक्त। देश में इस तरह का प्रयास प्रथम बार किया गया है।
- देश के 219 बारंबार सूखा से प्रभावित जिलों में भू–जल रिचार्ज, भू–जल की स्थिति में सुधार, मृदा नमी में सुधार तथा सूक्ष्म जल भंडारण सृजन के लिए रुपये 410 करोड़ (246 करोड़ रुपये राज्यों को विमुक्ति) का आवंटन प्रथम बार किया गया।
- क्षेत्रीय स्तर पर किसानों को जल के दक्षतापूर्वक उपयोग करने हेतु आत्मा कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु रुपये 50 करोड़ का आवंटन एवं राशि विमुक्त।

4. सॉयल हैल्थ कार्ड योजनाः

- किसान को उसकी जमीन की उर्वरक क्षमता की जानकारी देने के लिए मोदी सरकार ने देश में पहली बार सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम शुरू की है। इससे पहले कुछ राज्य अपने स्तर

पर यह स्कीम अलग–अलग तरीके से चला रहे थे। नमूने एकत्रित करने, उनका विश्लेकषण करने और सॉयल हैल्थ कार्ड द्वारा उर्वरक सिफारिशों में कोई एकरूपता (Uniformity) नहीं थी। सॉयल हैल्थल कार्ड के लिए अलग से राज्यों को राशि भी नहीं दी जाती थी।

- इस योजना के अंतर्गत 2 वर्षो के अंतराल में देश के सभी किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि विशेष फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त संस्तुति (Recommended) जैसे उचित मात्रा में उर्वरक एवं पोषक तत्व का प्रयोग करने और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देना। उचित सलाह देकर किसानों को अधिक उत्पादन करने में समर्थ बनाया जा सके ।
- इस स्कीम को वर्ष 2015–16 में 142 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2016–17 के लिए कुल 365.85 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, यह 155 प्रतिशत की वृद्धि है।
- साथ ही उर्वरक कम्पनियों के 2 हजार मॉडल खुदरा केन्द्रों को अगले 3 वर्ष में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएँ मुहैया करायी जायेंगी ।
- दिनांक 10.05.2016 तक के लक्ष्य 1.13 करोड़ सॉयल नमूने के लक्ष्य की तुलना में 107 लाख नमूने एकत्रित किये जा चुके हैं जिससे 5.91 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड बनाये जा रहे हैं। इनमें से 2 करोड़ कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, शेष की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2016–17 में 146 लाख नमूना संग्रह करना है जिससे 8.07 करोड़ कार्ड बनाये जायेंगे।

5. परंपरागत कृषि विकास योजना :

- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार परंपरागत कृषि विकास योजना को आरंभ किया। वर्ष 2016–17 में 297 करोड़ रूपये की केंद्र सरकार के कुल आवंटन के साथ व्यापक जैविक कृषि स्कीम जिसके अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 250 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रावधान है जो कि पिछले वर्ष से 19 प्रतिशत अधिक है। अभी तक राज्य सरकारो ने लगभग 8000 क्लस्टर भी बना लिए गये हैं।
- उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रंखला विकास हेतु तीन वर्षों के लिए 400 करोड़ रूपये का आवंटन वर्ष 2015–16 में हुआ, यह 125 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ वर्ष 2015–16 में शुरू की गयी। जैविक खेती की योजना को आगे बढाने में सहायता करेगा। शेष 275 करोड़ रुपये अगले वर्ष (2016–17 एवं 2017–18) की परियोजना की आवश्यकता को पूरा करेगी। साथ ही मनरेगा के तहत जैविक खाद के उत्पायदन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढ़ों का निर्माण किया जाएगा।

6. नीम लेपित यूरियाः

- मोदी सरकार ने एक वर्ष में देश में अब नीम कोटेड यूरिया 100 प्रतिशत उपलब्ध कराना

शुरू कर दिया है। इससे जो यूरिया अवैध रूप से रसायन उद्योग में जाता था, का दुरूपयोग समाप्त हो गया है। अब किसानों को यूरिया पर्याप्ता मात्रा में मिल रहा है। साथ ही नीम लेपित यूरिया के उपयोग से उत्पादन लागत में 10–15 प्रतिशत की भी कमी हो रही है।

7. कृषि वानिकी

- राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम हेतु पहली बार 2016–17 के बजट में 75 करोड़ केन्द्रांश का प्रावधान किया गया है। इससे 'मेड़ पर पेड़' अभियान को गति मिलेगी।
- बागवानी उत्पादन और प्रबंधन हेतु रिमॉट सेन्सिंग प्रौद्यौगिकी तकनीक का विकास कर किसानों को वर्ष 2014 से लाभ पहुंचाया जा रहा है।

8. किसानों के लिए मोबाइल एप की शुरुआत

- किसानों की सुविधा के लिए निम्नलिखित चार मोबाइल एप शुरु की गई है जो www.mkisan.gov.in के अलावा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- **किसान सुविधा** : किसानों को घर बैठे कृषि संबंधित सूचनाएं जैसेः मौसम, बाजार भाव, फसलों की बीमारियां व कीट की पहचान व उपचार, कृषि संबंधित विशेषज्ञ से सलाह।
- **पूसा कृषि** : कृषि एवं बागवानी की उन्नत किस्में तथा नवीनतम तकनीकियों की जानकारी।
- **एग्री मार्केट** : 50 किलोमीटर के दायरे में मंडियों में बाजार भाव की जानकारी।
- **फसल बीमा** : फसल बीमा से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध।

9. राष्ट्रीय कृषि बाजारः

- किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु मोदी सरकार ने रु. 200 करोड़ की लागत से मार्च 2018 तक सामान्य ई– मार्केट प्लेटफार्म शुरु करने के उद्देश्य से 585 नियंत्रित मंडियों के साथ 1 जुलाई, 2015 से 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' स्कीम की शुरुआत की तथा राज्यों से अनुरोध किया कि अपने मण्डी कानून में निम्नांकित संशोधन करें:
  - ई–व्यापार की अनुमति प्रदान करना।
  - मण्डी शुल्क का एकल बिन्दु पर लागू करना।
  - पूरे प्रदेश में व्यापार हेतु एकल लाइसेंस की वैधता।
- 17 राज्यों एवं संघ शासित राज्यों ने पूर्णतः / आंशिक परिवर्तन कर लिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, नागालैण्ड, हरियाणा और चंडीगढ़ (केन्द्रीय शासित क्षेत्र)

- 7 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेशों ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओड़ीशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय और 2 केन्द्रीय शासित क्षेत्र – पुडुचेरी व दिल्ली,
- 7 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में मंडी कानून नहीं है – बिहार, केरल, मणिपुर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दादर व नगर हवेली और दमन व ड्यू
- 2 राज्यों में मंडी कानून है परंतु लागू नहीं हैः जम्मू – कश्मीर, सिक्किम
- 31 मार्च 2016 तक 12 राज्य क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की 365 मंडियों के लिए और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए रू 159.43 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 6 राज्यों (गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश) की 183 मंडियों के लिए रू 46.37 करोड़ निर्मुक्त किए जा चुके है।
- इस स्कीम के तहत 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ई–ट्रेडिंग प्लेटफार्म को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 8 राज्यों (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, हरियाणा) की 21 मण्डियों में 25 जिन्सों के व्यापार हेतु ई–नाम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोड़ दिया गया है।
- अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 के मध्य 200 मंडियों को इस ई–ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से उपयोग के लिए जोड़ दिया जाएगा।
- अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 के मध्य अगली 200 मंडियों को इस ई–ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से उपयोग के लिए जोड़ दिया जाएगा।
- 31 मार्च, 2018 तक शेष 185 मंडियों को इस ई–ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से उपयोग के लिए जोड़ दिया जाएगा।

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम):

- वर्ष 2013–14 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत केवल तीन फसलें – चावल, गेंहू, दलहन शामिल थी। मोदी सरकार द्वारा इस मिशन के अंतर्गत सात फसलें– चावल, गेंहू, दलहन, जूट, गन्ना, कपास व मोटे अनाज शामिल किये जा चुके हैं।
- वर्ष 2013–14 तक एनएफएसएम के अंतर्गत 16 राज्य व 468 जिले सम्मिलित थे। मोदी सरकार के दौरान अब सभी 29 राज्यों व सभी 638 जिलों को सम्मिलित किया गया हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन की खेती जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में शुरु की गयी है।
- वर्ष 2015–16 में 1137 करोड़ रूपये के मुकाबले चालू वर्ष 2016–17 में 1700 करोड़ रूपये राशि का आवंटन है। यह वर्ष के लिए 50 प्रतिशत बढ़ी है एवं दलहन के लिए 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

11. मधुमक्खी विकास के लिए:

- एनबीबी को मधुमक्खी पालन विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में कुल रु. 5.94 करोड़ (2011–12 से 2013–14) की वित्तीय सहायता के एवज में पिछले दो वर्षों (2014–15 और 2015–16) में कुल रु. 10.42 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की गयी।
- 9434 किसानों/मधुमक्खीपालकों को वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन में प्रशिक्षित किया गया।
- 5639 मधुमक्खीपालकों/मधुमक्खीपालन और शहद समितियों/फर्मों कंपनियों आदि का पंजीकरण किया गया है।
- शहद उत्पादन 72,300 मीट्रिक टन (2012–13), 76,150 मीट्रिक टन (2013–14) व 80,530 मीट्रिक टन (2014–15) से बढ़कर 2015–16 में 86,500 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है।

12. ज्वाइंट लाएबिलिटी ग्रुप को वित्तीय सहायता:

- पिछले सरकार में अप्रैल 2007 से मार्च 2014 तक 7 वर्षों में 6.7 लाख ज्वाइंट लाएबिलिटी समूहों की तुलना में मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2016 (2 वर्षों) में 10.49 लाख समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।
- अप्रैल 2007 से मार्च 2014 तक 7 वर्षों में रु. 6630 करोड़ की संचित उपलब्धियों की तुलना में मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2016 (2 वर्षों) में रु. 10225 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता संयुक्त देय समूहों को प्रदान की गयी।

13. कृषि ऋण प्रवाह:

- **कृषि ऋण:** वर्ष 2015–16 के लिए 8,50,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसे बढ़ाते हुए सरकार ने कृषि ऋण का लक्ष्य वर्ष 2016–17 के लिए 900,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया है।
- **किसानों के लिए ब्याज छूट:** भारत सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले फसल ऋण के सम्बन्ध में बैंकों को 2 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाती है ताकि बैंक किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण लघु अवधि के लिए उपलब्ध करा सके। समय पर भुगतान करने से 3 प्रतिशत ब्याज पर अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार अंततः किसानो को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि फसल ऋण के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करना पडता है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** सभी पात्र किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए बिना किसी व्यवधान के समय पर ऋण प्रदान करने के लिए 31.10.2015 तक 7,38,91,679 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए, जिनके तहत 5,27,944 करोड रुपए के फसली ऋण

प्रदान किए गए। केसीसी को एटीएम के माध्यम से प्रचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए अब स्मार्ट कार्ड–सह–डेबिट कार्ड में बदल दिया गया है।

- **फसलोपरान्त ऋणों के लिए ब्याज छूट योजना का विस्तारः** सामान्यतः आर्थिक कमजोरी की वजह से किसान फसल को वेयरहाउस में नहीं रख पाते व मजबूरन अपने उत्पाद की बिक्री तत्काल कर देते हैं, उनके उत्पाद के भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले लघु एवं सीमान्त किसानों को वेयरहाउस में उनके उत्पाद रखने हेतु सिर्फ भण्डारण की रसीद दिखाने फसल ऋण को उसी दर पर 6 मास की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज छूट देने का प्रावधान किया गया है ।

- **प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ब्याज छूटः** भारतीय रिजर्व बैंक के स्थाई दिशानिर्देश के अनुसार प्राकृतिक आपदा की घोषणा पर लघु अवधि के फसल ऋणों के पुनर्संरचना हेतु प्रदान करता है । ऐसे फसल ऋणों की पुनर्संरचना उनको समयावधि में परिवर्तित करता है। परिणामस्वरुप फसल ऋण ब्याज की रियायती दर अर्थात प्रतिवर्ष की पूर्ति तक 7 प्रतिशत पर जारी रहेगा । इसके पश्चात ब्याज को सामान्य ब्याज दर पर लिया जाएगा। जैसा कि भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में निर्णय लिया कि प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित क्षेत्र में बैंकों द्वारा देय मुख्य राहत के सम्बंध में फसल हानि का मानदण्ड 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया है। बैंको को यह निर्देश दिया गया है कि बैंक अधिकतम 2 वर्ष (एक साल की मोरटोरियम अवधि सहित) तक पुनर्भुगतान अवधि में छूट प्रदान कर सकते हैं यदि नुकसान 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है। यदि फसल हानि 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो पुनर्भुगतान अवधि को 5 वर्ष (एक साल की मोरटोरियम अवधि सहित) तक के लिए पुनर्संरचित किया जा सकता है।

14. पशुपालन – डेयरी – चिकित्सा शिक्षा : श्वेत क्रांति

- देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' रु. 50 करोड़ की राशि आवंटित कर मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में प्रारम्भ किया गया है। इन राज्यों में 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना कर दी गई है तथा सांड़ों के उन्नयन हेतु 35 पशु प्रक्षेत्र को अधिक धन देकर आधुनिक बना दिया गया है। इसके साथ 3629 साड़ों को वीर्य संकलन हेतु आवंटित कर दिया गया है।

- ए2 दूध के विपणन की अलग व्यवस्था करने हेतु ओड़ीसा एवं कर्नाटक राज्यों को अलग से धन आवंटित कर दिये गये हैं।

- देसी नस्लों के विकास के लिए 2007–08 से 2013–14 तक केवल रु. 45 करोड़ इस कार्य के लिए खर्च किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा दिसंबर 2015 तक केवल डेढ़ वर्षों में 27 राज्यों से आए 35 प्रस्तावों के लिए रु. 582.09 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह धन पिछले दो वर्षों के दौरान 13 गुणा बढ़ा दिया गया है।

- दो नए राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर (एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत में) भी स्थापित किए जा रहे हैं जिसके लिए रु. 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन वर्ष 2013–14 में 137.61 मिलियन टन से वर्ष 2014–15 में 146.31 मिलियन टन हो गया व 2015–16 में 160 मिलियन टन अनुमानित है। विश्व में दुग्ध उत्पादन 10 वर्षों का औसत वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत है जबकि भारत का औसत वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत है। वर्ष 2014–15 के दौरान दुग्ध उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत था जबकि 2015–16 के दौरान दुग्ध उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर 9.59 प्रतिशत (अनुमानित) है।
- पशुओं के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका एवं मुंहपका रोग के लिए सुधरा प्रबंधन अपनाकर वर्ष 2013 की तुलना में 2015 में 377 प्रकोपों से घटाकर 109 कर दिया गया है।
- पशु चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से 46 की गई है तथा कॉलेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को 60 से बढ़ाकर 100 तक किया गया था। 17 पशु चिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या को 914 से बढ़ाकर 1,332 किया गया है। पशु चिकित्सा स्नात्तकोत्तर छात्रों में डेढ़ गुना की वृद्धि हासिल की गयी। पशु चिकित्सा विद्यालय में भी डेढ़ गुना सीटें बढ़ायी गयीं।
- **अलग से चार नई परियोजनाएं – नए बजट में** 'पशुधन संजीवनी' 'नकुल स्वास्थ्य पत्र', ई–पशुधन हाट और राष्ट्रींय देशी नस्ल जेनोमिक केन्द्रा के लिए 850 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन के लिए वर्ष 2016–17 में 1600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो 2015–16 में 1491 करोड़ रुपये थे।
- वर्ष 2015–16 के दौरान 81,879 मिलियन अंडों (अनुमानित) का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान 78,484 मिलयिन अंडो का उत्पादन हुआ था। अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत है।

15. नीली क्रांतिः

- मात्स्यिकी में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र में 'नीली–क्रांति' का आह्वान किया है। जिसके अनुरूप, इस क्षेत्र की सभी योजनाओं को समेकित करते हुए, एक छत्र योजना, 'नीली–क्रांति' का सृजन किया गया है।
- अंतर्देशीय व समुद्री मात्स्यिकी को 'नीली–क्रांति योजना' मे समेकित करते हुये सम्पूर्ण मात्स्यिकी सेक्टर के एकीकृत विकास को सुगम बनाया गया है। 'नीली क्रांति' मे

विशेष रूप से जलकृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग से, देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जलीय–संसाधनों से मछली–उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित है।

- 'नीली क्रांति' योजना हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए रु. 3000 करोड़ का केन्द्रीय बजट निर्धारित है।
- मछली–उत्पादन 2013–14 में 95.72 लाख टन से बढ़कर 2014–15 में 101.64 लाख टन (5.92 लाख टन की वृद्धि)।
- 2015–16 में अनुमानित उत्पादन 109 लाख टन (7.36 लाख टन अधिक)।
- 'बचत–सह–राहत' घटक के अंतर्गत दी जाने वाली राहत राशि जो वर्ष 2013–14 में पूर्व सरकार के दौरान रू. 600 प्रतिमाह थी, उसे मोदी सरकार ने वर्ष 2014–15 में बढ़ाकर रू. 900 प्रतिमाह किया, एवं 'नीली–क्रांति' योजना के बाद इसमें अब पुनः परिवर्तन करते हुए रु. 1500 प्रतिमाह कर दिया गया है।
- नीली क्रांति पर केंद्रीय क्षेत्र की मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबंधन योजना के अंतर्गत उत्तर–पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है।
- मछुआरों की वार्षिक बीमा प्रीमियम को 29 रूपये से घटाकर 20.27 रूपये कर दिया गया है, जिससे अधिक मछुआरों ने बीमा कराया है।
- मात्स्यिकी उत्पादन संसाधनों के विकास के लिए पिछले दो वर्ष की तुलना में 53.04 करोड़ रूपये को बढ़ाकर वर्तमान दो वर्ष में 77.36 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

16. कृषि अनुसंधानः

- खेतों में कार्यकुशलता बढ़ाने तथा खेती की लागत को कम करने के लिए कुल 9,067 नए कृषि उपकरणों के प्रोटोटाइप का विकास किया गया। वर्ष 2013 के मुकाबले इनकी संख्या बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई।
- पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति में तेजी लाने हेतु बिहार में देश का दूसरा "राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसन्धान केंद्र" की स्थापना।
- पूसा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर 68 साल में पहली बार बरही, झारखण्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IRAI) की स्थापना की गई एवं असम में भी स्थापना की जा रही है।
- गंगटोक, सिक्किम में देश का सबसे पहला राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- आज तक देश के 614 जिलों के लिए जिला आकस्मिक योजनाएं बनाकर राज्यों को उपलब्ध कराया गया है। इन्हें सूखा, बाढ़, ओला, पाला, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कृषि

उत्पाद के नुकसान को कम करने तथा किसानों की आजिविका सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

- नया मृदा परीक्षक विकसित किया गया जिससे संतुलित उर्वरक संस्तुति एवं त्वरित मृदा परीक्षण संभव हुआ।
- पालतू पशुओं की जैविक विविधता का अध्ययन कर 7 नई नस्लों की पहचान कर उनका पंजीयन किया गया जिनमें वेलाही एवं गंगातीरी गाय की, पंतजा बकरी की कच्चीकट्टी, काली भेंड़, खारी ऊँट, अगोण्डा गांव शूकर एवं मारवारी मुर्गे की नस्लें शामिल हैं।
- पशुओं की बीमारियों के शीघ्रातीशीघ्र पहचान हेतु ब्रुसेला, ब्लूटंग एवं खुरपका आदि बीमारियों की त्वरित पहचान के लिए नई कारगर विधियां विकसित की गई।
- पीपीआर, बकरियों का चेचक, स्वाईन फीवर एवं भेड़ के चेचक के लिए सुधरे एवं प्रभावशाली टीकों की खोज की गई।
- राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विशेषज्ञता सॉफ्टवेयर, बफेलोपीडिया, बकरी प्रबंधन सूचना तंत्र एवं ई–भैंस विज्ञान केन्द्र पर विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किए गयें।
- दूध में ए1ए1 तथा ए2ए2 की पहचान हेतु, दूध में मिलावट खोजने, कई प्रजातियों में पशुओं के माँ–बाप की पहचान करने हेतु आनुवंशिकी सिद्धांतों पर आधारित खोज किट विकसित किए गएं।
- **कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती को बढ़ावा**– वर्ष 2013–14 में 66 प्रतिशत भर्ती के मुकाबले 2014–15 व 2015–16 में लगातार 81 प्रतिशत भर्ती, खुली प्रतियोगिता से भर्ती प्रक्रिया को तेज किया गया व कृषि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी गयी।
- वर्ष 2015–16 में डेयर/भाकृअप को रु. 5387.95 करोड़ की कुल वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए जबकि वर्ष 2016–17 में इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि के साथ रु. 6309.89 करोड़ के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गए, जिससे शिक्षा, अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को गति मिलेगी।

17. पिछले दो वर्षों में उन्नत किस्मों के विकास संबंधी मुख्य बातें:

- वर्ष 2014 में अनाज, तिलहन, दलहन, रेशादार फसलों और चारा फसलों की कुल 74 उन्नत किस्में और वर्ष 2015 में 81 उन्नत किस्में खेती के लिए जारी की गईं।
- धान एवं गेहूं सहित अनाजों की 96 किस्में, रेशेदार फसलों की 3, चारा फसलों की 9 तथा गन्ने की 3 किस्में विकसित की गईं।
- इनमें आयरन व जिंक से भरपूर धान की उन्नत किस्म डीआरआर धान 45, और प्रोटीन की उच्च मात्रा के साथ सीआर धान 310 एवं हीरा नाम की धान किस्म क्रमशः बारानी

परिस्थितियों के लिए और अगेती परिपक्वता अवधि वाली प्रमुख किस्में हैं।

- धान की सूखा प्रतिरोधी उन्नत किस्म आईआर–64 DRt 1 (डीआरआर धान–42) को बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में खेती के लिए जारी किया गया।
- रतुआ की प्रतिरोधी व आयरन व जिंक की अधिक मात्रा वाली गेहूं की उन्नत किस्म एचडी 2967 को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में समय से बुवाई वाले सिंचित क्षेत्रों में खेती के लिए जारी किया गया।
- दलहन की 20 तथा तिलहन की 24 अधिक उपज देने वाली तथा रोग सहिष्णु व रोग प्रतिरोधिता वाली किस्में जारी की गईं। इनमें दलहन की कम समय में पकने वाली और बड़े बीजों वाली मसूर की उन्नत किस्म राज विजय लेन्टिल 31 तथा इन गुणों वाली मूंग की उन्नत किस्म डीजीजीवी–2 प्रमुख हैं।
- सरसों की नई किस्म 'पूसा मस्टर्ड 30' तथा इसके तेल को व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया। इस किस्म में हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इरूसिक अम्ल की मात्रा 2 प्रतिशत से भी कम है जबकि सामान्य सरसों की किस्मों में यह मात्रा 40 प्रतिशत से अधिक पाई जाती है।
- तिलहन की प्रजातियों में उच्च पैदावार के अतिरिक्त, तेल की मात्रा भी अधिक है।
- पूर्व में हानिकारक रसायनों के कारण प्रतिबंधित खेसारी दाल की 3 नई किस्में यथा रतन, प्रतीक, महातेवरा विकसित की गईं, जिनमें हानिकारक रसायन ओएडीपी की मात्रा नगण्य है। नई व सुरक्षित खेसारी दाल किस्मों की खेती के प्रसार के लिए पहल की जा रही है।
- विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों, तकनीकियों, कृषि रीतियों के बारे में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1400 प्रशिक्षण आयोजित कर कुल 60,600 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- दलहन फसलों की उन्नत किस्मों व तकनीकों के प्रसार के लिए गत दो वर्षों में दलहनी फसलों के अंतर्गत 33,282 हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल करते हुए कुल 1,38,099 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किए गए।
- तिलहन फसलों के संबंध में 41,668 हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल करते हुए कुल 1,04,565 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किए गए।

18. कृषि शिक्षाः

- पूर्वोत्तर भारत की अपार क्षमताओं को पहचानते हुए मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अंतर्गत छः नए कॉलेज खोले गये। इससे पूर्वोत्तर भारत में कृषि कॉलेजों की संख्या में पिछले दो वर्षों में लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

- इसी प्रकार बुंदेलखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के अंतर्गत 4 नए कॉलेज खोले गए।
- बिहार के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके तहत चार महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
- विभिन्न राज्यों में उच्च कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो वर्षों में आठ नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। वर्ष 2013 की तुलना में नई सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 में भाकृअनुप द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकी।
- ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (Rural Agricultural Work Experience - RAWE) इस योजना के तहत उत्पादन, संरक्षण तथा मार्केटिंग बाधाओं की पहचान करने तथा किसानों के साथ कार्यानुभव के लिए छात्रों की स्कॉलरशिप को वर्ष 2016 से रु. 750/– से बढ़ाकर रु. 3000/– प्रतिमाह किया गया।
- राष्ट्रीय प्रतिभा स्कॉलरशिप (National Talent Scholarship) के तहत वर्ष 2016 से अंडर ग्रेजुएट छात्रों की स्कॉलरशिप को रु. 1000/– से बढ़ाकर रु. 2000/– प्रतिमाह किया गया तथा नई पहल करते हुए वर्ष 2016 से पीजी छात्रों (जो गृह राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं) को रु. 3000/– प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि इन्हें पहले कोई स्कॉलरशिप /वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी।
- वर्ष 2013 के मुकाबले कृषि कॉलेजों में अनुभवजन्य लर्निंग इकाइयों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले दो वर्षों (2014–15 एवं 2015–16) के शिक्षा बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में 6 नये कॉलेज खोले गये, जबकि रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 4 नये विश्वविद्यालय खोले जायेंगे। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार के 4 नये कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है।
- राजस्थान में कृषि एवं हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।
- स्नातक छात्रों की राष्ट्रीय प्रतिभा स्कॉलरशिप को दोगुनी एवं स्नातकोत्तर छात्रों की स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी।

19. कृषि विज्ञान केन्द्र (कृषि विस्तार):

- कृषि विज्ञान केन्द्रों को पहली बार सुदृढ़ करने का कार्य प्रारंभ किया गया जिसके तहत प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्मिकों की संख्या 16 से बढ़ाकर 22 की गई है।
- 195 केवीके में मृदा एवं जल नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं, 183 केवीके में वर्षाजल

संग्रहण ढांचा, 221 केवीके में बुनियादी प्रसंस्करण सुविधाएं एवं 109 केवीके में लघु स्तर पर बीज प्रसंस्करण सुविधा दी जाएगी। 400 केवीके पर मोबाइल मृदा परीक्षण किट उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

- वर्ष 2013 के मुकाबले वर्ष 2015 में कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए बजट में लगभग 50 प्रतिशत अधिक धनराशि आवंटित की गई। 59 बड़े जिलों में तथा 5 पर्वतीय जिलों में किसानों को बेहतर सुविधा पहुंचाने हेतु दूसरा केवीके स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- नई सरकार की पहल पर 6 नए केवीके स्थापित किए गए। इसके अलावा 49 नए केवीके खोलने के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से 20 के लिए स्थल चयन कर लिया गया है।
- केवीके के कार्य की देखरेख के लिए वर्ष 2013 तक केवल आठ जोनल परियोजना निदेशालय ही थे। नई सरकार ने निदेशालयों की संख्या आठ से बढ़ाकर ग्यारह कर दी है और साथ ही निदेशालय को अधिक प्रभावी बनाते हुए इन्हें कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान (अटारी) के रूप में उन्नत किया गया। तीन नए संस्थान पटना, गुवाहाटी एवं पुणे में स्थापित किए जा रहे हैं।
- पहली बार दलहन विशेष मिशन के अंतर्गत 474 केवीके द्वारा दलहनी फसलों पर तथा 299 केवीके के द्वारा तिलहनी फसलों पर उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 60 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 100 केवीके में दलहन हब स्थापित किया गया, जिसको बढ़ाकर 2016–17 में 150 करने का प्रस्ताव है।
- 444 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा देश भर में किसान सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिसमें 34 केन्द्रीय मंत्रियों एवं विभिन्न राज्यों के 262 सांसदों, 23 मंत्री एवं 168 विधायकों ने भाग लिया।
- 384 कृषि विज्ञान केन्द्रों में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को सक्रिय किया गया तथा सॉयल हेल्थ कार्ड योजना को मजबूती प्रदान करने के लिए 400 मिनी मोबाइल मृदा परीक्षण मशीनें स्थापित की गईं।
- पहली बार देश भर में 5 दिसम्बर, 2015 को कुल 607 कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं भाकृअनुप. के 80 संस्थानों/राज्य कृषि विश्व विद्यालयों में विश्व मृदा दिवस का आयोजन करके किसानों को मृदा स्वास्थ्य तथा संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर कुल 2.5 लाख मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार कर किसानों को वितरित किए गए। मिट्टी की तुरंत जांच तथा संतुलित उर्वरकों की सिफारिश के लिए पहली बार आईटी आधारित मृदा परीक्षक किट का विकास किया गया तथा 400 केवीके को यह किट दिया गया है।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों व संस्थानों पर आयोजित सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण समारोह (5 दिसम्बर, 2015) में 97 सांसदों, 184 विधायकों, 10 केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों के 34 मंत्री, 1 राज्यपाल व 2 मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 454 कृषि विज्ञान द्वारा देश भर में किसान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजित की गयी। इन सम्मेलनों में देश भर के किसानों के अलावा 34 केन्द्रीय मंत्रियों, 262 सांसदों और विभिन्न राज्यों के 166 विधायकों ने भाग लिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों को बनाने के लिए 3 नये जोनल परियोजना निदेशालय बनाये गये तथा जोनल परियोजना निदेशालय योजना को अधिक सक्षम बनाने हेतु उनको कृषि प्रौद्योगिकी व अनुपयोग अनुसंधान संस्थान का दर्जा दे दिया गया।
- खरीफ किसान सम्मेलन 330 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें माननीय सांसदगण एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तकनीकी फिल्मों को प्रदर्शित किया गया एवं संबंधित साईट्स का वितरण, तकनीकी उत्पादों का प्रदर्शन आदि को संपादित किया गया। खरीफ के द्वारा आयोजित किसान सम्मेलनों में 1,54,495 किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। रबी मौसम के दौरान 500 कृषि विज्ञान केंद्र पर रबी किसान सम्मेलन आयोजित किये गये हैं।
- वैज्ञानिकों का किसानों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए पहली बार, देशभर में भाकृअनुप. के संस्थानों और केवीके में दिनांक 23–29 दिसम्बर, 2015 के दौरान जय किसान–जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया।
- मेरा गांव – मेरा गौरव योजना को गांव तक वैज्ञानिक कृषि की प्रभावी तथा व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों को शामिल कर प्रारंभ किया गया है। इस उद्देश्य के लिए चार–चार वैज्ञानिकों के 5,000 समूह एक वर्ष में 25,000 गांवों से सम्पर्क करेंगे। अभी तक 15,000 ग्रामों में कृषि वैज्ञानिक सम्पर्क कर नयी तकनीकी जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए रु. 50 लाख की कुल पुरस्कार राशि के साथ 643 कृषि विज्ञान केन्द्रों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बड़े एवं पर्वतीय जिलों में दो के.वी.के. खोलने की योजना है।
- **कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाये रखना:** आर्या परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कृषि के विभिन्न कृषि उद्यमों, स्थायी आय, समृद्ध सेवा क्षेत्र और लाभकारी रोजगार के लिए सशक्त और आकर्षित किया जाएगा। यह परियोजना कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 22 राज्यों के 22 जिलों में चलाई जा रही है।
- **फार्मर फस्ट:** फार्मर फस्ट का उद्देश्य किसान–वैज्ञानिक इंटरफेस, प्रौद्योगिकी एकीकरण अनुप्रयोग और प्रतिक्रिया, साझेदारी और संस्थागत निर्माण तथा पाठ्य सामग्री सम्भरण को समृद्ध करना है। यह किसान और वैज्ञानिक के मध्य संबंध, क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक अनुकूलन तथा अनुप्रयोग, ऑन साइट इनपुट प्रबंधन, संस्थागत निर्माण और प्रतिक्रिया के लिए मंच प्रदान करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान के 100 संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा 1 लाख किसानों के साथ सीधे तौर पर कार्य करने के लक्ष्य की शुरुआत कर दी गई है।

- **किसान मोबाइल परामर्श**: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एम–किसान पो. र्टल का उपयोग करके कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा एसएमएस के माध्यम से 90 लाख किसानों को विभिन्न फसलों के उन्नत पैकेज तथा संबद्ध उद्यमों, मौसम आधारित परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं की सूचना प्रदान की गई है। हाल ही में कृषक समुदाय के लाभ के लिए दो मोबाइल एप्स –किसान सुविधा और पूसा कृषि को शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 2013–14 तक चावल, गेहूँ एवं दलहन फसल अब मोटे अनाज, गन्ना, जूट एवं कपास शामिल हो गये हैं। 19 राज्य शामिल थे, अब 29 राज्य हो गये हैं। 482 जिले शामिल थे, अब 638 जिले शामिल हो गये हैं।
- राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल ताड़ मिशन 2013–14 में 14 राज्य थे, अब 24 राज्य शामिल हैं।

तिलहन पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन

तिलहन फसलों की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख तिलहनी फसलों पर 300 कृषि विज्ञान केन्द्रों को शामिल करते हुए बढ़ी संख्या में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन प्रारंभ किये गये। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल मिलाकर 11,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल करके 28,000 से भी अधिक अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किए गये। वर्ष 2016–17 तक इस योजना में लगभग 400 युवाओं को जोड़ा जाएगा।

दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये नये कदम

- पूर्वी भारत में "हरित क्रान्ति " योजना के अंतर्गत चावल परती क्षेत्रों में दलहन फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- चावल के खेतों में मेड़ पर अरहर की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- 500 से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा फसल प्रदर्शन।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों में 150 सीड हब बनाना।
- ब्रीडर सीड का अधिक उत्पादन।
- बीज मिनिकीटों का वितरण।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैव–उर्वरक एवं बायो एजेन्ट यूनिट्स।
- दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि।

दलहन पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन

- दालों की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख दालों पर 475 कृषि विज्ञान केन्द्रों को शामिल करते हुए बड़ी संख्या में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन प्रारंभ किए गए। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल मिलाकर 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 60,000 से भी अधिक प्रदर्शन आयोजित किए गये।

दलहन बीज हब

- दलहन केन्द्रों की स्थापना भागीदारी विधि से आई.सी.ए.आर. संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से की जायेगी।
- प्रत्येक दलहन केन्द्र मूल गुणवत्ता युक्त बीज मुहैया करायेगा तथा इन्हें पड़ोसी किसानों के लिए उपलब्ध करायेगा।
- प्रत्येक केन्द्र से 1000 क्विंटल दलहन का उत्पादन होगा।
- प्रारंभ में वर्ष 2016–17 के दौरान 100 दलहन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जिनकी संख्या वर्ष 2017–18 के दौरान बढ़ाकर 150 की जायेगी।

फसल विज्ञान

- बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए फसलों की उन्नत किस्में।
- अनाज दलहन एवं तिलहन फसलों की उन्नत किस्मों के विकास पर बल।
- इन किस्मों में पोषण रोग प्रतिरोधिता, जलवायु अनुकूलन, सूखा सहिष्णु तथा अगेती परिपक्वता जैसे गुण।
- जनवरी 2012 से दिसम्बर 2013 तक 187 और जनवरी 2014 से दिसम्बर 2015 तक 227 तथा जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक 80 नई किस्में जारी की गई।

जलवायु सहिष्णु किस्में (सूखा प्रतिरोधी एवं बाढ़ सहनशील)

- वर्ष 2014 से 2016 तक अनाज 19, दलहन 20 एवं तिलहन 24 विकसित की गई।ज

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रजनक बीज की आपूर्ति

- किसानों को स्वस्थ और प्रमाणिक बीज प्रदान करने के लिए फसलों के प्रजनक बीजों के उत्पादन पर बल दिया गया।
- वर्ष 2013–14 में 9,000 टन।
- वर्ष 2014–15 में 9,800 टन।

सूखा प्रभावित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बैठक के बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह की प्रेस विज्ञप्ति।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने सूखा प्रभावित राज्यों से अपील की है कि वे सूखा से लड़ने के लिए तुरंत कदम उठाएं और उसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें। उन्होंने ये बात आज नयी दिल्ली में कृषि मंत्रालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही।

कृषि मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ दो–दो घंटे बैठक कर इतनी गंभीरता दिखाई है और सूखे से जूझ रहे लोगों को तत्काल राहत देने के साथ – साथ अकाल, पानी एवं कृषि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ अलग–अलग बैठक कर रहे थे। प्रधानमंत्री की आखिरी बैठक 21 मई को ओड़ीशा के मुख्यमंत्री के साथ हुई। इसके पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सूखा प्रभावित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बाद विचार के विषय निम्नाकिंत हैं।

- प्रधानमंत्री जी ने सूखा झेल रहे राज्यों से आग्रह किया कि वे उन समस्याओं पर तुरंत काम करें जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। राज्यों से कहा गया कि वे सूखे की मौजूदा समस्या, सूखे को लेकर की गयी अब तक कार्रवाई और सूखे का सामना करने के लिए साप्ताहिक आधार पर तैयार प्रस्तावित उपायों सहित सूखे से बचने के दीर्घकालिक योजना बनाएं। बार–बार सूखा झेलने वाले राज्यों को अलग से इस पर काम करना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया गया कि वे पेयजल की कमी और अभाव, संरक्षण प्रयासों तथा विद्यमान जल संसाधनों का इष्टतम और सावधानीपूर्वक उपयोग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए साप्ताहिक आधार पर कार्य योजना तैयार करें। इसकी तैयारी और कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों से जल संरक्षण और जल सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार/प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे फार्म तालाबों का निर्माण करें, सूक्ष्म सिंचाई अपनाने और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की ओर अग्रसर होने के लिए एक बड़ा अभियान चलाएं। राज्य जल भंडारण और जल संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा दें और जल निकायों का कायाकल्पन करें। खोदे जाने वाले कुंओं तथा फार्म तालाबों का संवर्धन किए जाते समय राज्य सिंचाई के लिए सोलर पंपों को प्रोत्साहित करें।

- जल संरक्षण, सिंचाई तालाबों की गाद निकाले जाने, वर्षा जल संचयन, भूमिगत जल रिचार्ज, पनधारा विकास इत्यादि के लिए एकीकृत कार्य योजना विकसित की जानी है। रोक बांधों, रिसन तालाबों का रख रखाव, नहरों की लाईनिंग, वितरण नेटवर्क में जल रिसाव तथा चोरी को रोकने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जल उपयोग को प्राथमिकता; व्यर्थ जल के पुनःचक्रण तथा इसका अर्ध शहरी इलाकों में कृषि के लिए उपयोग को बढ़ावा देना।
- गन्ने को चरणबद्ध तरीके से सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर करना। किसानों को इसके स्थान पर दूसरी फसलें बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।
- देश के विभिन्न भागों में निष्क्रिय परंपरागत/ऐतिहासिक स्टेप वैल्स की बहाली पर विशेष जोर।
- सभी जल निकायों को एक विशेष पहचान देकर उन पर संख्या डाला जाना।
- भूमिगत पाइप लाइनों का निर्माण करके कमान क्षेत्र में बीच बीच में टूटी हुई नहरों को जोड़ना। इससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा वाष्पीकरण से होने वाली हानियों में कमी आएगी।
- जल की कमी से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासनिक निकायों को शामिल करके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय शुरू करेंगे। यह निर्णय लिया गया कि मानसून के आने से पहले जल संरक्षण के लिए तैयारी से संबंधित कदम उठाए जाएंगे।
- किसानों को 'मोबाइल ऐप' पर उनकी भाषा में जिला–वार आकस्मिकता योजनाएं, मौसम से संबंधित सूचना, फसल संबंधी परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे।
- भूमिगत जल संसाधन का पता लगाने के लिए विकेंद्रीकृत कंटूर एंड रिज मैपिंग के लिए व्यापक रूप से रिमोट सेंसिंग, सैटलाइट प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
- क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए मृदा सायॅल हेल्थ कार्ड का विश्लेषण और उपयोग तथा फसलों के लिए वैज्ञानिक सलाह जो ऐसे क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक अनुकूल हो।
- तटीय क्षेत्रों में समुद्री शैवाल पालन, मोती और झींगापालन को प्रोत्साहित करना।
- मिल्क रूट के साथ साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाना।
- शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग के ऊपर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाना।
- फसल विवधिकरण के अलावा राज्य मूल्य वर्धन तथा वैकल्पिक आजीविका–डेयरी, कुक्कुट पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पुष्प कृषि, इमारती लकड़ी के वृक्ष उगाना आदि को बढ़ावा देने पर विचार करेंगे।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अधिक और कम जोखिम वाले जिला समूह बनाएं और विभिन्न फसलों के तहत बोये गए क्षेत्र तथा बीमित क्षेत्र के बीच होने वाली त्रुटि को समाप्त करें।

By adopting modern scientific farming, we can boost national economy in a big way.

- Shri Narendra Modi
Prime Minister

Doubling the fund allocation for agriculture:

An amount of Rs. 35894 cr is allocated in current year for the welfare of farmers as compared to Rs. 15809 cr last year. For irrigation Rs. 20,000 cr corpus fund has been created in collaboration with NABARD. For the year 2016-17, Rs. 12517 cr has been allocated to complete 23 schemes.

How will farmers be benefitted?

- The premium under Prime Minister Fasal Bima Scheme has been reduced significantly with full coverage of loss.
- Under Prime Minister Krishi Sichai Yojana, improved irrigation facilities are being created with long term irrigation fund, better management of ground water resources and creation of more ponds and wells.
- To reduce the pressure of loan on farmers, Rs. 15,000 cr has been allocated for interest subvention.
- The flow of agriculture credit has been increased to 9.0 lakh crores.
- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for connecting village roads.
- Policy decision has been taken to improve the condition of sugarcane farmers.
- For development of rural infrastructure, Shyama Prasad Mukherjeee Rurban Mission initiated.
- Direct Benefit Scheme has been launched to help needy people, to remove middlemen and encourage social security.
- National Agriculture Market, a pilot project based on e-trading platform for agriculture was launched through which farmers can sell their produce with greater ease and obtain best prices.
- Remote sensing technology has been developed to boost horticulture production and help farmers to adopt better technologies.
- Under National Food Security Mission rice, wheat and pulses were included. Now, coarse crops, jute, cotton and sugarcane, have been included to boost production.
- To help poor farmers, government has increased its efforts on bee keeping.
- To supply quality and pure seed, capacity of National Seed Corporation has been enhanced.

- Government is giving greater emphasis on white and blue revolution.
- Entrepernurship development in poultry production: Under National Livestock Develompment Mission, a component of Entrepenrushiip and creation of Employment (EDEG) scheme with activities on poultry production, creation of poultry breeding farms, including that of Duck, Turkey, Gunea fowl, Japanese quil, feedstore, feed mills, feed analytical laboratories, facilities for grading eggs and their packing is being run for increasing exports. Government has strengthened its activities on these lines.
- Greater emphasis is also being given on Agriculture Research, Education and Extension.
- Under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Scheme – farmers and villages are provided with separate electric feeder.
- Deen Dayal Antyodya Mission
- Atal Pension Yojana
- Neem coated urea to enhance fertilizers use efficiency and prevent misuse.
- Kisan TV- 24X7 channel for farmers to provide information on whether Kisan Mandi and other data.
- Grant of Rs. 2.87 lakh crores to Gram Panchayats and Nagar Palikas. This is a tremendous increase of 228% over 5 years of previous UPA Government.
- Digital Literacy Programme: additional 6 crore households would be covered.
- A surcharge of 7.5% would be imposed on black money in the form of 'Agriculture Welfare Surcharge' which will be used for development of agriculture and rural economy.
- Target for sanctioned fund under Prime Minister Mudra Yojana has been developed to Rs. 1.80 lakh crore.
- Announcement of Rs. 2000 crore in the budget for providing LPG connection to poor females. Five crore families will be benefitted in next three years.
- Stand Up India launched for 2.5 lakh SC-ST and women entrepreneurs.
- 3,000 outlets would be opened under Prime Minister Jan Aushadhi Yojana during 2016-17.

1. PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA:

- With the initiatives of the Hon'ble Prime Minister, short-comings in the Crop Insurance Scheme have been removed and a new scheme – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been approved for implementation across the country.
- This is the **biggest financial support** till date by the Central Government in Crop Insurance.
- Farmers will now have to pay the **lowest premium till date** for availing Crop Insurance. The balance premium burden will be borne by the Government - even if it is more than 90% of the total premium.
- For food-grains, pulses and oilseeds, there will be one season – one rate for the farmer. Different rates for different crops for different districts has been removed. For Kharif: maximum 2% and for Rabi: maximum 1.5% premium is to be paid by farmers.
- **Farmers will get full financial security** – there will be no capping on the premium rates and no reduction in the sum insured.
- In case farmer is unable to sow/transplant due to bad weather, he would be entitled to get claims.
- For the first time, risk of post harvest losses upto 14 days occurring due to cyclone, unseasonal rainfall and local calamities such as hailstorm, landslide & inundation have been included for coverage across the country.
- For the first time, mobile and satellite technology will be used for correct estimation and quick payment of claims to farmers.
- Under this scheme, provisions have been made for creation of mass awareness and publicity through media so that the number of insured farmers can be increased from present 20% to 50% in the next 2-3 years.
- An allocation of Rs. 5500 cr in the 2016-17 budget has been made under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana which was Rs. 3185 crore in previous budget. This is an increase of about 73 % in this scheme.

2. CHANGE IN THE NORMS FOR PROVIDING RELIEF IN CASE OF DISASTER :

- To provide relief to the distressed farmers in case of disasters, Modi Government has revised the norms for providing relief. Earlier, the relief

was to be given only when the damage to the crop due to disaster was 50% or more. Now this relief is being given in case of 33% damage to the crop. The amount of compensation under various heads has also been increased by 50%.

- A historical decision has been taken, whereby for foodgrains damaged due to excessive rainfall, full minimum support price will be paid. While the families of the deceased persons were given a compensation of only Rs.1.50 lakh as per the earlier norms, Modi Government has increased the same to Rs.4 lakh.
- For the years 2010-2015, a provision of Rs.33580.93 crore was made for State Disaster Response Fund. The same has been increased to Rs.61219 crore for the period 2015-2020. An am ount of Rs. 2551 cr. has been released as 1st instalment to 10 drought affected states for 2016-17. This amount can be used for fodder or water supply in animal camps, fodder to animals outside camps, repair of hand pump and ring well purposes.
- Similarly, UPA Government during the four years 2010-11, 2011-12, 2012-13 & 2013-14 approved a relief of only Rs.12516.20 crore as against Rs. 92043.49 crore demanded by the States affected by drought and hailstorm. The Modi Government in year 2014-15 alone approved an amount of Rs.9017.998 crore as relief to the States affected by drought and hailstorm as against their demand of Rs. 42021.71 crore. During the year 2015-16, Rs.13,497.71 crore have already been approved for till now as against a demand of Rs. 41722.42 crore.
- Under NDRF, there was no separate scheme for providing assistance to Union Territories (UTs). Keeping this in mind, Modi Government has during 2015-16 made an allocation of Rs. 50 crore for UTs.

3. PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(PMKSY):

- With the objective of developing a long term solution for mitigating the effect of drought, PMKSY has been launched. This programme is being implemented jointly by three ministries.
- This scheme is to be implemented in mission mode. 28.5 lakh hectare area will be brought under irrigation for which a sum of Rs. 5717 crore has been earmarked for the year 2016-2017. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has obtained Rs. 2340 crore in place of Rs. 1550 crore as compared to the year 2015-2016 and this is an enhancement of 51%.

This amount will be used for micro irrigation (drip and sprinkler), drought proofing and water conservation activities.

- An area of 4.3 lakh hectares and 4.3 lakh hectares was brought under micro irrigation during 2013-14 and 2014-15 respectively.
- An area of 5.7 lakh hectares has been brought under micro irrigation during 2015-16. For the year 2016-17, a target of 8.3 lakh hectares has been kept.
- 89 large and medium irrigation projects are pending since 15-20 years long. In the next five years, an amount of Rs. 86,500 cr is required to complete these projects to irrigate an area of 80.6 lakh hectares.
- During the year 2016-17, a sum of Rs. 12517 crore will be incurred to implement 23 irrigation schemes.
- Besides this year through NABARD it has been decided to create a fund of Rs. 20,000 crore for irrigation and expeditious implementation.
- Under MNREGA, 5 lakh farm ponds and wells will be instituted in rain fed areas.
- This programme has been started with the objective of making irrigation water available to every farmer and every farm.
- Template for DIPs developed and shared with states for bringing in uniformity in planning process.
- It is targeted that 235 district irrigation plans have been prepared by 31st March, 2016. The district irrigation plans of all the remaining districts would be prepared by 30th September, 2016.
- Rs. 65.40 cr released to all districts of States/UTs for preparing DIPs for the year 2015-16.
- During the year 2015-16, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare has allocated a sum of Rs. 175 cr to cope with the problem of ground water in the country. The said fund will be utilized for 150 Blocks identified by central ground water board to supplement material component in water related works under MNREGA. This initiative has been taken for the first time in the country.
- For the first time a sum of Rs. 410 cr (Rs. 246 cr has been released to the states) has been allotted meant for ground water recharge, improving the status of ground water, improving the status of moisture contained in soil

as well as micro water storage so as to face the problems prevailed in drought hit 219 districts in the country.

- A sum of Rs. 50 cr has been allocated and released for the training through the program called as ATMA so as to ascertain better use of water for farmers on regional basis.

4. SOIL HEALTH CARD SCHEME :

- Soil Health Card Scheme has been taken up for the first time by Modi Government to provide information to farmers on fertility status of their soil. Earlier some of the States were implementing this scheme at their own level in different ways. There was no uniformity in sample collection, testing and fertilizer recommendation through soil health cards. Money also was not separately given to states earlier.
- Under this scheme, soil health card will be provided to all farmers of the country at an interval of two years. It will indicate appropriate recommendation of nutrients dosages to be used for crop production and will enable the farmers to improve their soil health and its fertility.
- Under this scheme a sum of 368 crore rupees has been allocated for the year 2016-17 as compared to 142 crore rupees in the year 2015-2016 which is an increase of 155%.
- 2000 model retail outlets of fertilizers companies will be opened in the forthcoming three years for soil testing and fertilizer recommendation.
- As on 10.05.2016 against a target of 1.13 crore soil samples, 107 lakh soil samples have been collected from which 5.91 crore soil health cards are being made. Out of these, 2 crore soil health cards have been distributed to the farmers and remaining are under process. During 2016-17, 146 lakh samples are to be collected from which 8.07 crore soil heath cards will be prepared.

5. PARAMPARAGAT KRISHI VIKAS YOJANA:

- First time, Modi Government has launched Paramparagat Krishi Vikas Yojana to promote organic farming . During 2016-17, an allocation of Rs. 297 cr has been made by the Central Government and it has been increased 19% from the allocation of Rs. 250 cr for the year 2015-16. As of now, State Governments have made 8000 clusters.

- **Organic value chain for North Eastern States** a sum of rupees 400 crore has been allocated in 2015-2016 for the forthcoming three years meant for the development of North Eastern States and organic value chains. This scheme has been initiated with the allocation of rupees 125 crore in 2015-2016 which will pave the way for the growth of Organic Agriculture Scheme. The remaining Rs. 275 crore will meet the needs of the projects being conducted in the next year (2016-17 and 2017-18). Alongwith 10 lakh compost ditches will be prepared for organic manure under MNREGA.

6. NEEM COATED UREA:

- In one year, Modi Government has made 100% neem coated area available in the country. Due to this diversion of urea to Chemical Factories has been stopped. Now farmers are getting urea in adequate quantity. Besides this, the cost of production is being reduced by 10-15% with the use of neem coated urea.

7. AGROFORESTRY:

- For the first time, during 2016-17 a budgetary provision of Rs. 75 crore has been made for National Agroforestry Program which will accelerate the program “Med Par Ped”.
- Remote sensing technology is being used since 2014 to provide technical inputs to farmers in the field of horticulture production and management.

8. INITIATION OF MOBILE APP FOR FARMERS:

- Following four mobile apps have been launched for the welfare of farmers which can be downloaded from google play store as well as from www.mkisan.gov.in
- Facilities for farmers : The farmers can obtain information sitting at home about weather, market prices, crop diseases, identification & treatment of pests along with the advice from agricultural experts.
- PUSA Agriculture: Information about improved varities of agriculture and horticulture as well as latest techniques.
- Agri Market : Information about prevailing prices in the mandis spread within 50 kms.
- Crop Insurance: All information related to crop insurance is available.

9. NATIONAL AGRICULTURE MARKET:

- In order that farmers produce may fetch the best prices, Government of India has launched the National Agriculture Market Scheme on 1st July 2015 with Rs. 200 crores, with the aim to integrate 585 regulated markets with the common e-market platform by March 2018 and States are advised to carry out the following amendments in their marketing laws:
  - Allowing e-marketing
  - Single point levy of market fees
  - Single unified licence for trading across the States.
- These 17 States / Union Territories have completed / partially modified their APMC Act: Andhra Pradesh, Gurajat, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Goa, Madhya Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Mizoram, Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Nagaland, Haryana & Chandigarh (UT Region).
- These 7 States and 2 UTs have not made any change in APMC Act: West Bengal, Tamil Nadu, Odisha, Arunachal Pradesh, Tripura, Assam, Meghalaya and two UTs – Puducherry & Delhi
- There is no APMC Act in 7 States / UTs: Bihar, Kerala, Manipur, Andman & Nicobar Islands, Lakshwadeep Islands, Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu.
- There are APMC Act in two States but not implemented: Jammu & Kashmir and Sikkim.
- By 31st March, 2016 approval had been granted for a total of Rs. 159.43 crore towards integration of 365 Markets of 12 States namely Gujarat, Maharashtra, Telangana, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chandigarh (UT), Uttar Pradesh, Haryana, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh with National Agriculture Market (NAM) and for implementation of the NAM Platform by the Strategic Partner. This including an amount of Rs. 46.37 cr which has been released for 183 mandis of 6 States namely Gujarat, Telangana, Jharkand, Chhattisgarh, Rajasthan & Madhya Pradesh.
- Under this Scheme, the e-trading platform has been operationalized on 14th April, 2016 on the hundredth birth anniversary of Dr. Bhim Rao Ambedkar in which 21 mandis of 8 States (Gurajat, Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Jharkhand &

Haryana) have been connected with e-NAM pilot project for trading of 25 agriculture commodities.

- Between April 2016 - September 2016, 200 markets will be integrated with this e-trading Portal.
- Between October, 2016 - 31st March 2017, the next batch of 200 Mandis will be integrated with this e-trading Portal.
- Remaining 185 Mandis will be integrated with this e-trading Portal by 31st March 2018.

10. National Food Security Mission (NFSM):

- Till 2013-14 only three crops were covered under National Food Security Mission namely – Rice, Wheat & Pulses. The coverage during Modi Government has been increased to seven crops namely – Rice, Wheat, Pulses, Jute, Sugarcane, Cotton & Coarse Cereals.
- Till 2013-14 only 16 States and 468 districts were covered under NFSM. During Modi Government, all the 29 States and all 638 districts have been covered under NFSM.
- Pulses cultivation under NFSM has been taken up in J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand and all North Eastern States.
- Budgetary allocation for National Food Security Mission as against Rs. 1137 cr in 2015-16, Rs. 1700 cr has been allocated in the current year. It is an increase of 50 % and Rs. 500 cr. has been provided for pulses.

11. DEVELOPMENT OF BEEKEEPING :

- Approved an amount of Rs. 10.43 crores to National Bee Board (NBB) during last two years(2014-15 & 2015-16) in comparison to an amount of Rs. 5.94 crores during last three years(2011-12 to 2013-14);
- 9434 farmers/ beekeepers have been trained in scientific beekeeping;
- 5634 beekeepers/ beekeeping & honey societies/ firms/ companies etc. have been registered;
- Honey production increased from 72,300 MTs in 2012-13, 76,150 MTs in 2013-14 & 80,530 MTs in 2014-15 to 86,500 MTs in 2015-16 (estimates).

12. FINANCING OF JOINT LIABILITY GROUPS (JLGS):

- Financing of 10.49 lakh Joint Liability Groups from April 2014 to March, 2016 during just 2 years of Modi Government as compared to 6.7 lakh JLGs from April 2007 to March 2014 during the 7 years of previous government.
- In comparison to cumulative achievement of Rs. 6630 cr. from April 2007 to March, 2014 during 7 years of previous Govt., Rs. 10225 cr. were made available to JLGs between April 2014 and March, 2016 during just 2 years of Modi Government.

13. AGRICULTURAL LOAN FLOW:

- Agriculture Credit : The Agriculture Credit Target for the year 2015-16 was fixed at Rs.850,000 crore. The Government has increased the target to Rs.900,000 crore for the year 2016-17.
- Interest subvention to Farmers: The Government provides to banks 2% interest subvention on crop loan so that the banks are able to advance to the farmers short term crop loan of up to Rs.3.00 lakh at 7% interest per annum. For prompt repayment of the crop loans, additional interest subvention of 3% is provided to the farmers. Thus, the effective interest rate for the short term crop loan is 4% per annum.
- Kisan Credit Cards Scheme: In order to ensure that all eligible farmers are provided with hassle free and timely credit for their agricultural operation, 7,38,91,679 Kisan Credit Cards have been issued as on 31.10.2015, thereby providing them short term crop loan of Rs.5,27,944 crore. KCCs have now been converted into Smart Card cum Debit Cards to facilitate its operation through ATMs.
- Extension of Interest Subvention for post harvest Credit: In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses against warehouse receipts, the benefit of interest subvention scheme has been extended to small and marginal farmers having Kisan Credit Card for a further period upto six months post harvest on the same rate as available to crop loan against negotiable warehouse receipt for keeping their produce in warehouses.
- Interest Subvention in Natural Calamities situation: Reserve Bank of India (RBI) announces Standing Guidelines to banks for restructuring of crop loan in areas affected by natural calamities. Banks have been advised to convert all short-term crop loans into term loan. 7% interest is levied on

such converted loans for the first year. Thereafter the interest at normal rate of interest is charged. As decided by the Government in April, 2015, the benchmark for initiating relief measures by banks has been reduced to 33% crop loss from 50% crop loss in the areas affected by natural calamities. Banks have been advised to allow maximum period of repayment of upto 2 years (including the moratorium period of 1 year) if the crop loss is between 33% and 50%. If the crop loss is 50% or more, the restructured period for repayment is extended to a maximum of 5 years (including the moratorium period of 1 year).

14. ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & VETERINARY EDUCATION:

- With a view to conserve and develop indigenous bovine breeds, Rashtriya Gokul Mission, a new initiative under National Programme for Bovine Breeding and Dairy Development has been launched for the first time in the country, with an allocation of Rs 50 crore for Madhya Pradesh and Andhra Pradesh.
- Funds have been allocated to Orissa and Karnataka for separate marketing arrangements of A2 type milk.
- Since 2007-08 to 2013-14, a meagre amount of only Rs 45 crore was spent for the development of indigenous breeds. Whereas, the current Government has in only one and a half years, upto December 2015, has approved 35 projects from 27 States and has sanctioned Rs 582.09 crore. This amount has been increased by more than 13 times in the last two years.
- Two National Kamdhenu Breeding Centre, one in northern region and other in southern region are being established in the country with an allocation of Rs 50 crores.
- India is number one in milk production in the world. Milk production has increased from 137.61 million tonnes during 2013-14 to 146.31 million tonnes during 2014-15 and during 2015-16 milk production is projected to 160 million tonnes. During past 10 years, world milk production on an average increased by 2.2% annually while in India milk production has increased by 4.6% annually. During 2014-15 annually milk production rate was 6.3 % while during 2015-16 milk production rate is projected to 9.59 million tonnes annually.

- Under Livestock Health Improvement program, the number of Foot and Mouth Disease (FMD) outbreaks has come down from 377 in 2013 to 109 in 2015.
- In order to meet the shortage of trained veterinary manpower, the number of veterinary colleges has increased from 36 to 46. Intake of students in various Veterinary Colleges was enhanced from 60 to upto 100 seats. Total number of seats has been increased to 1,332 from 914 in 17 Veterinary Colleges. The number of veterinary graduates has increased by one and half times. Similarly the seats in veterinary colleges have increased by one and half times. One and a half time increase in post graduate studies in veterinary education has been attained. Seats in veterinary colleges have been increased by one and a half time.
- **Four New Projects** – Rs. 850 crore have been provided for in the new budget, Livestock Sanjivani, Nakul Swasthan Patra, e-livestock haat and Rastriya Indiginous Breeds Genomic Centre.
- An amount of Rs. 1600 crore hast been allocated for Animal Husbandry, Diary and Fisheries for 2016-17 which was Rs. 1491 crore in 2015-16.
- During the year 2015-16, 81,879 million eggs (projected) produced while during 2014-15, 78,484 million eggs were produced. Egg production is now increasing by 5% annually.

15. BLUE REVOLUTION :

- Realizing the immense scope for development of Fisheries, the Modi Government has heralded 'Blue Revolution' in this Sector. Accordingly, an umbrella Scheme namely 'Blue Revolution' has been formulated by merging all the ongoing schemes in this sector.
- Integrated development of entire fisheries sector has been made easy by consolidating Inland and Marine Fisheries under the 'Blue Revolution' scheme. Main focus of Blue Revolution is to increase fish production from aquaculture by introduction of advanced technologies and through utilization of vast fishery resources available in the country.
- For Blue Revolution scheme, central budget of Rs. 300 crore is earmarked for five years.
- Fish production has increased from 95.72 lakh tones during 2013-14 to 101.64 tonnes during 2014-15 (an increase of Rs.5.92 lakh tones).

- The fish production for 2015-16 is estimated at 109 lakh tones (an increase of 7.36 lakh tones).
- The amount of Rs. 600 per month being provided under 'Saving-cum-Relief' component during 2013-14 by the previous Government, has been increased by the Modi Government to Rs. 900 per month during 2014-15, and it has been further revised to Rs. 1500 per month under Blue Revolution scheme.
- Under the sector of 'Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries' central financial assistance to North Eastern States has been increased from 75 percent to 80 percent.
- The annual insurance premium of fishermen has been reduced from Rs 29 to Rs 20.27 as a result of which majority of the fishermen have got insurance done.
- An amount of Rs 77.36 crore are being used in two years for the development of fish production resources which is a substantial increase over the earlier amount of Rs 53.04 crore.

16. AGRICULTURE RESEARCH:

- To increase the efficiency and reduce total cost of farming, a total of 9067 prototypes of new agricultural equipment were developed. As compared to 2013, the number has almost doubled.
- To accelerate the progress of second green revolution in Eastern India, second such centre "National Centre for Integrated Farming Research" is being setup in Motihari, Bihar.
- For the first time in 68 years, an Indian Agriculture Research Institute (IARI) has been established at Barhi, Jharkhand on the line of PUSA Research Institute, New Delhi and another is being establishing in Assam.
- It has been decided to establish first National Organic Agricultural Research Institute in Gangtok, Sikkim.
- District Contingency Plans have been made prepred and made available to 614 districts in the country. These are being implemented with the objective to mitigate losses to agriculture produce due to natural calamities like drought, flood, hailstorm etc. and to protect the livelihood of the farmers.
- New soil testing (Mrida Parikshak) Kit developed for rapid soil testing and balance fertilizer recommendation.

- Analysis of Livestock Biodiversity of domestic animals resulted in identification and registeration of 7 new breeds including Belahi and Gangatiri cattle, Pantja Goat, Katchaikatty Black Sheep, Kharai Camel, Agonda Gaon Pig and Marwari Chicken.
- Diagnostic Kits for immediate diagnosis of LFA for Brucellosis, Elisa for Bluetongue, DIVA kit for FMD developed.
- Improved and effective vaccines developed for Peste des Petites Ruminants (PPR), Goat Pox Vaccine, Classical swine fever and sheep pox.
- Special software developed on National Animal Disease Referral Expert System (NADRES), Buffalopedia, Goat Research Info System and e-Buffalo Science Centre.
- Molecular Kits for identification of A1A1 and A2A2 alleles and adulteration of milk, identification of parentage on genetic principles developed.
- **Increase in recruitment of scientists** – 81 % recruitment in 2014-15 and 2015-16 in comparison to only 66% in 2013-14, accelerated recruitment process through open competition and increase in representation of women scientists.
- A total financial resources of Rs. 5387.95 crore was provided to DARE/ ICAR in the year 2015-16 whereas in the year 2016-17 financial resources of Rs. 6309.89 crore has been made available with an increase of about 17 % compared to the last year which will give impetus to education, research and agricultural extension.

17. IMPORTANT POINTS FOR ADVANCED VARIEITIES DEVELOPED IN 2 YEARS:

- In 2014, total 74 improved varieties of cereals, pulses, oilseeds, fibre crops, forage crops and sugarcane were released for commercial cultivation, while in 2015, total 81 improved varieties of these crop groups were released for farmers.
- Combining both the years, total 96 improved varieties of cereals, nine of forage crops and three each of fibre crops and sugarcane were released.
- Among them, zinc mineral enriched improved variety of Rice, namely DRR Dhan 45, for the states of Southern India and high protein containing another Rice variety, namely CRR Dhan 310, for both irrigated and rainfed condition in both Kharif and Rabi/bodo seasons were prominent ones.

- Another prominent improved rice variety tolerant to drought/low soil moisture, namely IR 64-DRt-1 was released for commercial cultivation in Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana states.
- A rust disease resistant improved variety of Wheat suitable for late sowing irrigated condition, namely HD 3059, was released for commercial cultivation for the entire state of Punjab, Haryana and Delhi and in some selected agro-ecologies of Rajasthan, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand.
- Disease tolerant/resistant and high yielding 20 improved varieties of pulses and 24 improved varieties of oilseeds were released for commercial cultivation during this period. They included large seeded and moderately wilt resistant variety of kabuli chickpea, namely Vallabh Kabuli Chana-1; early maturing and large seeded lentil variety, namely Raj Vijay Lentil 31, and early maturing and large seeded mungbean variety, namely DGGV-2.
- Yellow mosaic virus and charcoal rot diseases resistant high yielding soybean variety, namely JS 20-29 was released for major soybean growing states like Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.
- An improved variety of Indian mustard with good oil quality, namely Pusa Mustard 30, was licensed for commercialization. This variety contains less than 2% erucic acid fatty acid in comparison to more than 40% erucic acid found in Indian mustard varieties, in general. This fatty acid is considered harmful to cardiac health.
- Improved varieties of Oilseeds released for cultivation in last two years are potentially higher seed and oil yielder.
- Three improved varieties of Khesari dal namely Ratan, Prateek and Mahateora with very low level of ODAP neurotoxin compound were developed, as the crop is facing ban for sale due to higher concentration of this compound in traditional varieties. Actions were initiated for dissemination of these varieties of Khesari dal, which are safe for human consumption.
- In order to create awareness and knowledge among farming community about improved varieties and agro-production technologies of different crops, 1400 training programmes were organized and total 60600 farmers were trained.

- In the past two years, total 138099 frontline demonstrations on improved varieties and production technology of pulses and 104565 frontline demonstrations on improved varieties and production technology of oilseeds were organized by the scientists at the farmers' fields, in 33282 ha and 41668 ha area, respectively, to create scientist-farmer interface for faster dissemination of agri-technology.

18. AGRICULTURAL EDUCATION :

- Recognizing the enormous potential of North-East India, six new colleges were opened by Modi government under Central Agricultural University, Imphal. Due to this, the number of agricultural colleges in the Northeast region has increased by almost 85 percent in the last two years.
- Similarly, in the Bundelkhand region, 4 new colleges were opened under Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi.
- On the lines of Pusa Research Institute, New Delhi, for the first time in 68 years, Indian Agricultural Research Institute (IARI) was established in Barhi, Jharkhand and now one more is being set up in Asom.
- To promote higher agricultural education in different states, Modi government has established eight new agricultural universities. Compared to 2013, due to the efforts of the new government, in 2015, there was nearly 41 percent increase in the intake of students in the State Agricultural Universities through ICAR.
- Rural Agricultural Work Experience (RAWE) is aimed to provide real life experience and opportunity to work with farmers and identify production, protection and marketing constraints, industrial attachment, inplant training etc. the scholarship for the work experience students has been increased from Rs. 750/- to Rs. 3000/- per month from the year 2016.
- Under the National Talent Scholarship (NTS) the financial assistance to the Under Graduates has been increased from Rs. 1000/- to Rs. 2000/- per month and a new initiative for scholarship of Rs. 3000/- per month has been taken for the Post Graduates who go for ready in other State from the year 2016.
- Compared to 2013, the number of empirical learning units in agricultural colleges increased by almost 50 percent. Education budget has been increased by 50% in the last two years (2014-15 & 2015-16)

- Six new colleges have been opened in Central Agricultural University, Imphal and four new colleges are being opened in Rani Laxmi Bai Central Agricultural University in Bundelkhand region. Four new colleges are also proposed to be opened in Rajendra Central Agricultural University, Bihar.

Establishment of agricultural university in Rajasthan and horticulture university in Haryana is under process.

Doubling of National Talent Scholarship for graduate students and increase in scholarship of post graduate students.

19. KRISHI VIGYAN KENDRA(KRISHI EXTENSION):

- Efforts were made for strengthen the KVKs by enhancing the number of staff positions of KVKs from the existing strength of 16 to 22.
- The facility for Soil and Water Testing labs in 195 KVKs, Rain Water Harvesting Structures in 183 KVKs, Minimal Processing Facilities in 221 KVKs and seed processing facility on small scale in 109 KVKs will be established. Mobile soil testing kits have been provided to 400 KVKs.
- About 50 % financial assistance has been enhanced to the KVK system in 2015 as compared to 2013. 109 new KVKs including 59 KVKs in larger districts and 5KVKs in mountain districts will be established.
- Six new KVKs have been established on the initiative of the new Government. Besides these, proposals to open 49 new KVKs have been obtained from States out of which site selection has been completed for 20 KVKs.
- There were only 8 Zonal Project Directorates up to 2013 to monitor the KVKs. The new Government has increased this number to 11 and to make these Directorates more effective, these have been upgraded as Agricultural Technology Application Research Institutes. Three new institutes are being established at Patna, Guwahati & Pune.
- For the first time, under the special mission on Pulses and Oilseeds, 474 KVKs on pulses and 299 KVKs on oilseeds have demonstrated advanced technologies on farmer's field. These frontline demonstrations are being conducted in more than 60000 acres area. Pulses Hubs have been established in hundred KVKs which is proposed to be increased to 150 in 2016-17.
- Kisan Sammelans and demonstrations were conducted in 444 KVKs across the country in which 34 Central, 262 MPs, 23 state ministers and 168 MLAs participated.

- Soil testing laboratories activated in 384 KVKs and 400 mini mobile soil test machines have been established to strengthen soil health card scheme.
- For the first time in the country, World Soil Day was organised on December 5, 2015 by 607 KVKs and 80 ICAR Institutes/ SAUs to educate the farmers about soil health and use of recommended fertilizers. On this occasion, about 2.5 lakh soil health cards were prepared and distributed to the farmers. A Soil testing kit was developed for quick analysis of soil samples to optimise the use of fertilisers. This soil testing kit has been provided to 400 KVKs.
- 97 MPs, 184 MLAs, 10 Union Ministers, 34 ministers from States, 1 Governor and 2 Chief Ministers participatedin the Soil health card distribution function organised by KVKs on December 5, 2015.
- Awareness campaign on Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was held in all the KVKs of the country during April 2016 to bring about awareness among the farmers. Peoples' representatives including 34 central and state ministers, 262 MPs and 166 MLAs participated in these programmes.
- Three new zonal project directorates have been opened for setting up KVKs and were given the status of agriculture technology and application research institute to enhance their capacity.
- Kharif Farmer Conference was organized by 330 KVKs which was attended by Hon'ble MPs and local people's representative. On this occasion, technical films were displayed by KVKs and distribution of related sites, showcase of technical products, etc. were published. 1,54,495 farmers participated in the Kharif Kisan Conference. Rabi Farmer Conference was organized by 500 KVKs during the Rabi season.
- To strengthen the interface between farmers and scientists, Jai Kisan Jai Vigyan Week was celebrated for the first time during December 23-29, 2015.
- Mera GaonMera Gaurav programme has been initiated to effectively promote direct interface of scientists of ICAR Institutes and State Agricultural Universities with the farmers to hasten the lab to land process. For this, a group of four scientists each will adopt 5 villages. Thus, there will be nearly 5000 groups of scientists adopting 25000 villages. At present, agricultural scientists have started providing information on newer technologies to the farmers in 15000 villages.

- A competition of national level will be organized among 643 KVKs with a total award amount of Rs. 50 lakh for bringing reforms in the efficiency and performance of the KVKs.
- **Attracting and Retaining Youth in Agriculture (ARYA):** The ARYA project will attract and empower the Youth in Rural Areas to take up various Agri-enterprises in Agriculture, allied and service sector for sustainable income and gainful employment. The project is running in 22 districts of 22 States through KVKs.
- **Farmer FIRST:** The Farmer FIRST aims at enriching Farmers –Scientist interface, technology assemblage, application and feedback, partnership and institutional building and content mobilization.It will provide a platform to farmers and scientists for creating linkages, capacity building, technology adaptation and application, on-site input management, feedback and institution building. The scientists from 100 ICAR Institutes/ Universities are proposed to work with one lakh farmers directly.
- **Kisan Mobile Advisory:** By usingmKisan portal of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, the KVKshave sent SMSsto more than 90.0 lakh farmers on improved package of practices of various crops and allied enterprises, weather based advisories and information on various Government schemes. Recently two Mobile Apps –KisanSuvidha and PusaKrishi have also been launched for the benefit of farming community.
- Apart from Rice, Wheat and Pulses, Coarse Cereals, Sugarcane, Jute and Cotton have been added under National Food Security Mission. Initially 19 states were included which has been increased to 29. Initially 482 districts were included in this scheme which has been increased to 638.
- Initially 14 states were covered under National Mission on Oilseeds and Oilpalm during 2013-14 which has been increased to 24 states.

Oilseeds Demonstration:

- To meet the growing demand of oilseeds, large number of frontline demonstration have been initiated on 300 KVKs. More than 28,000 demonstrations covering 11,000 hectare of land were conducted during 2015-16. In 2016-17, 4000 youth will be involved in this scheme.

Steps to increase production of pulses:

- Pulses crop being encouraged in rice fallow areas under 'Bringing Green Revolution in Eastern India' scheme.
- Summer moong cultivation being promoted.
- Pegion pea on rice bunds being encouraged.
- Crop Demonstration through more than 500 KVKs.
- 150 seed hubs in Krishi Vigyan Kendras.
- Enhanced breeder seed production.
- Distribution of Seed Minikits.
- Bio-fertilizer and bio-agent units in State Agricultural Universities.
- Substantial increase in MSP of pulses.

Pulses Demonstration:

- To meet the growing demand of pulses, large number of frontline Demonstration have been initiated involving 475 KVKs on major pulses more than 60, 000 demonstrations covering 22,000 hectare of land were conducted during 2015-16.

Pulses Seed Hub:

- Pulses Seed Hubs will be established with involvement of ICAR Institutes, Agricultural Universities and KVKs in participatory mode.
- Pulses hubs will provide basic quality seeds to neighbouring farmers.
- Each hub will produce 1000 Quintals of Pulses Seeds.
- Initially 100 Pulses Seed Hubs will be established during 2016-17 and it will be enhanced to 150 during 2017-18.

Crop Science:

- Improved varieties of crops for enhanced productivity.
- Emphasis on development of improved varieties of cereals, pulses, oilseeds crops.
- These varieties are having traits related to nutrition, disease-resistance, climate-resilient, drought tolerance and early maturing.

- Between January 2012 to December2013, 187 and January 2014 to December 2015, 227 new varieties were released while between January 2016 to April 2016, 80 new varieties have been released.

Climate Resilient Varieties (Drought resistant and floor tolerant)

- During 2014 to 2016, 19 varieties of food grains, 20 of pulses and 24 of oilseeds have been developed.

Supply of Breeder Seed by ICAR:

- Emphasis on production of breeder seeds of different crops to provide healthy and certified seeds to farmers.
- 9000 tonne in the year 2013-14.
- 9800 tones in the year 2014-15.

Prime Minister Shri Narendra Modi meetings with Chief Ministers of 11 drought affected states and subsequent press release of Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Radha Mohan Singh

- Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Radha Mohan Singh appealed to the drought-affected states that they take immediate steps to fight drought and review it on week to week basis. He said this while briefing press reporters at a press conference in the Ministry of Agriculture, in New Delhi, today.
- Agriculture Minister said that for the first time in our country, Prime Minister sat with chief ministers of 11 drought affected states for as long as two-hour and has shown such seriousness with giving immediate relief to the people suffering from famine , water - scarcity and had detailed discussions on agriculture .
- Agriculture Minister said that Prime Minister Shri Narendra Modi met Chief Ministers of the 11 drought affected states separately over last fortnight. The last meeting of the Prime Minister was on May 21 with Chief Minister of Odisha. Earlier, Prime Minister met chief ministers of Andhra Pradesh, Chhattisgarh. Telangana, Jharkhand, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan and Karnataka.
- Important points after discussion with Prime Minister and Chief Ministers of drought affected states.
- The Prime Minister engaged the State Governments on issues that needed immediate resolution. The problems faced currently, action taken and the proposed steps- short term on weekly basis, long term mitigation along with drought proofing measures specific to individual States were discussed in detail.
- Each State was requested to prepare an Action Plan on a weekly basis to tide over challenges like shortage and scarcity of drinking water, conservation efforts and usage of existing water resource optimally and prudently. For its preparation and implementation, the States were requested to use innovation/ technologies to address the challenge of water conservation and water security.
- States were requested to undertake a major drive for construction of farm ponds, adopt micro irrigation and diversify into crops requiring less water. The States would promote water storage and water conservation practices and rejuvenate water bodies. While promoting dug wells and farm ponds, the State will incentivise solar pumps for irrigation.

- Integrated action plan to be developed for water conservation, desiltation of irrigation tanks, rain water harvesting, ground water recharge, watershed development etc. Maintenance of check dams, percolation tanks, lining of canals, prevention of water leakage and pilferage in distribution network to be given priority.
- Prioritize water use; promote recycling waste water & use it for agriculture purpose in periurban areas.
- To cover sugarcane under micro-irrigation in a phased manner Farmers to be incentivised for its substitution.
- Special emphasis on reviving defunct traditional/historical step wells in different parts of the country.
- All water bodies to be numbered by assigning a unique identity.
- Completion of the missing links of canals in command area by constructing underground pipelines will be encouraged. This will reduce evaporation losses besides dispensing with the requirement of land acquisition.
- To tackle water scarcity, short term and long term measures, will be taken both by Centre and the State involving Local Self Government. It was decided that preparatory steps for water conservation would be completed before the onset of monsoon.
- District wise Contingency Plans, information on weather, crop advisories will be made available to farmers on 'mobile app' in their language.
- Remote Sensing, Satellite Technology will be used extensively for decentralised contour and ridge mapping and for locating ground water resource.
- Analysis and use of Soil Health Card for mapping of regions and scientific advice for crops which best suit such regions.
- Encourage the culture of seaweed, pearl and prawn culture in coastal areas.
- Beekeeping to be encouraged along the milk route.
- Rain water harvesting on building in urban areas to be made compulsory.
- Apart from crop diversification, the States will consider value addition and promotion of alternate livelihood- dairy, poultry, fishery, bee-keeping, floriculture, timber farming etc.
- On the issue of Pradhna Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), the States were advised to make clusters of high risk and low risk Districts. While implementing PMFBY, it was also impressed upon the State Governments to make use of technology to validate the crop cutting experiment and eliminate the error between area sown and area insured under different crops.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

http://agricoop.nic.in

पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग

http://dahd.nic.in ; http://dadf.gov.in

किसानों के लिए पोर्टल

http://farmer.gov.in

किसानों के लिए मोबाइल सेवाएं

http://mkisan.gov.in

किसान कॉल सेंटर

1800-180-1551

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

http://www.icar.org.in